POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 जनवरी, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! गरीबी एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के 75वें साल में भी देश का पीछा नहीं छोड़ रहा। आज भी यह एक बहस का विषय बना हुआ है। हाल ही नीति आयोग द्वारा गरीबी सूचकांक रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है।

रिपोर्ट के मुताबिक देश में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीब हैं। राजस्थान के आंकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं है। यहां बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में आधी से ज्यादा आबादी गरीब हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 35 फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। करीब 42 फीसदी लोग कुपोषण से ग्रस्त हैं। यह तो महज एक बानगी है।

विडंबना है, हर साल सरकारें नई-नई योजनाओं का पिटारा खोलती है, उनमें गरीबी मिटाने की बातें भी की जाती हैं। बावजूद इसके भारत दुनिया का सबसे असमान आय वाला देश बना हुआ है। यहां गरीब दिन प्रतिदिन कंगाली की ओर तो अमीर और ज्यादा धनवान हो रहा है।

विश्व असमानता रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के 50 फीसदी लोग महज सालाना 53,610 रुपए कमा पाते हैं। निचले तबके के लोगों की कमाई इस साल 13 फीसदी तक और घटी है।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

ऐसे में ये सभी आंकड़े क्या हमें चिंतित नहीं करते? कोरोना काल में तो गरीबों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हुई है। इस दौर में बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं और अब रोजगार की कमी से भी जूझ रहे हैं।

गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए कारगर तरीके से लागू करना जरूरी हो गया है।

'कट्स' ने दायर की प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर एनजीटी में याचिका

'कट्स' द्वारा नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल (एनजीटी) में हॉकिंग पर नियंत्रण और निजी व रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की है। याचिका में राजस्थान सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। एनजीटी ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के गृह, परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं मुख्य सचिव के नाम नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

उक्त याचिका पर्यावरण संरक्षण के तहत ध्वनि प्रदूषण, खासतौर पर वाहनों द्वारा 'हॉकिंग' से उत्पन्न शोर को लक्ष्य बनाते हुए दायर की गई है। गौरतलब है कि 'कट्स' पिछले कुछ अरसे से ध्वनि प्रदूषण और हॉकिंग पर नियंत्रण के लिए अभियान चला रहा है और सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व के माध्यम से पैरवी भी की है। याचिका में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया है कि 'हॉकिंग' मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इनकी कड़ाई से पालना नहीं होने से यह देश की सड़कों पर अभिशाप बन गया है। अनाधिकृत रूप से वाहनों में 'प्रेशर हॉर्न' का उपयोग इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं।

याचिका में एनजीटी से यह भी मांग की गई है कि पूर्व में दिल्ली सरकार को दिए गए फैसले के अनुरूप 'हॉर्कर्स' पर पर्यावरण मुआवजा राजस्थान में भी लागू किया जाए और पर्यावरण हितार्थ 'पर्यावरण कोष' के नाम अलग से कोष बनाया जाकर वसूली गई मुआवजा राशि उसमें जमा की जाए।

साइबर ठगी: एसबीआई बैंक को भारी पड़ा मैसेज नहीं भेजना

मालवीय नगर निवासी श्रीराम मीणा ने जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-4 में एसबीआई बैंक के खिलाफ परिवाद दायर किया। उन्होंने दर्ज परिवाद में आयोग को बताया कि उनके एसबीआई बैंक खाते से 09 अप्रेल से 13 अप्रेल 2017 के बीच साइबर ठगों ने एक लाख 28 हजार रुपए निकाल लिए। मोबाइल पर 13 अप्रेल को राशि निकासी का मैसेज मिलने पर उन्होंने बैंक जाकर ऑनलाइन खरीदारी को रुकवाया। इससे उनके खाते में 42 हजार 525 रुपए तो वापस जमा हो गए, लेकिन उन्हें 86 हजार 275 रुपए का नुकसान हो गया। यदि उन्हें बैंक द्वारा समय पर मैसेज दिया होता तो उन्हें यह नुकसान नहीं होता।

मामले की सुनवाई पर दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि मैसेज भेजने के लिए बैंक 15 रुपए शुल्क वसूलता है। अगर समय पर मैसेज मिलता तो ठगी से बचा जा सकता था। आयोग ने इसे सेवादोष करार दिया और एसबीआई बैंक को आदेश दिया है कि साइबर ठगों द्वारा निकाली गई 86 हजार 275 रुपए की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित परिवादी श्रीराम मीणा को वापस की जाए। साथ ही 15 हजार रुपए बतौर मानसिक संताप और 10 हजार रुपए परिवाद व्यय के भी अलग से अदा करने का निर्देश दिया है।

'कट्स' द्वारा राज्य स्तरीय जैविक मेला आयोजित

'कट्स' द्वारा संचालित जैविक खेती परियोजना के तहत पारीक कॉलेज, जयपुर में राज्य स्तरीय जैविक मेला आयोजित किया गया। मेले में प्रदेश के 30 जिलों से आए किसानों ने अपनी जैविक उत्पादों की स्टॉल लगाई। जिनमें किसानों द्वारा देशी वर्मी कम्पोस्ट खाद और देशी कीटनाशकों से तैयार खाद्यान्न, फल, सब्जियां और जैविक आहार आदि की प्रदर्शनी लगाई गई।

मेले में स्थानीय उपभोक्ताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और जैविक उत्पादों की जमकर खरीददारी की। उपभोक्ताओं का कहना था कि जहां रासायनिक विधि से तैयार खाद्यान्न के उपभोग से लोग कैंसर जैसी अनेक बीमारियां से ग्रस्त हो रहे हैं, वहीं जैविक खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और अनेक बीमारियों से रक्षा करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जैविक उत्पाद मिलते कहां हैं। आगन्तुक उपभोक्ताओं ने 'कट्स' के कार्यक्रम अधिकारियों और किसानों से इस बारे में जानकारी ली। मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से 5 बजे तक किया गया था।

घूसखोरी में राजस्थान अव्वल नंबर पर

भ्रष्ट देशों की सूची में भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है। यहां हर दूसरे व्यक्ति ने रिश्वत देने की बात मानी है। भारत में 74 फीसदी लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल में रिश्वतखोरी बढ़ी है। यहां अधिकारी कर्मचारी और नेता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शिकंजे में फंस रहे हैं।

वर्ष 2020 में देश भ्रष्टाचार के मामले में 77वें स्थान पर था। ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की हालिया रिपोर्ट में अब भारत 82वें स्थान पर है। इंडिया करप्शन सर्वे के अनुसार घूसखोरी में राजस्थान सबसे आगे है। यहां 78 फीसदी लोगों ने काम के बदले रिश्वत देने की बात मानी है। लोगों ने माना है कि पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल और बिजली पानी जैसी सेवाएं भी बिना घूस के नहीं मिलती।

ई-मैप और ई-वर्क पर ग्रामीण विकास

प्रदेश में मनरेगा समेत संचालित ग्रामीण विकास की करीब 20 हजार करोड़ रुपए के बजट वाली योजनाओं के लिए निगरानी और योजना बनाने का काम अब रीयल टाइम प्रक्रिया से हो सकेगा। इसके लिए ई-वर्क एवं ई-मैप मोबाइल एप शुरु किया गया है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज की प्रमुख सचिव अपर्णा अरोड़ा ने देते हुए कहा कि प्रदेश के 33 जिले, 352 पंचायत समिति, 11 हजार 326 ग्राम पंचायतें एवं 46 हजार 118 गांवों में विभाग की 25 से अधिक योजनाएं संचालित है। अब इन एप के जरिए ग्रामीण विकास की कार्य योजना बनाने और निगरानी तक सभी कार्य एकल प्लेटफॉर्म से हो सकेंगे। मोबाइल एप का उपयोग ग्राम विकास अधिकारी से लेकर शासन स्तर तक के सभी अधिकारी कर सकेंगे।

बाड़मेर: गांवों की बदली तस्वीर

बाड़मेर जिले के गडरारोड, लालासर, कुबड़िया, गिराब, आसाड़ी समेत करीब एक दर्जन गांवों में पानी की धार ने पांच हजार किसानों की तकदीर बदल दी है। सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र के कारण यहां नया सिंचित क्षेत्र विकसित हो रहा है। यहां पर पांच सौ से छह सौ फीट की गहराई पर मीठा पानी निकल रहा है। इसे प्रकृति का करिश्मा और अच्छा संकेत माना जा रहा है।

हालांकि भूजल विभाग ने इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर रखा है। फिर भी बॉर्डर के गांवों में हर साल दो सौ ट्यूबवैल खुद रहे हैं और अथाह पानी निकल रहा है। पिछले पांच साल में दो हजार से भी ज्यादा ट्यूबवैल खोदे गए हैं और भरपूर पानी से किसान सालाना लाखों रुपए की रबी की फसलें ले रहे हैं।

ग्रामीण घरों में पहुंचेगा शुद्ध पेयजल

जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 2345 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। राजस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए 10,180.50 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष आवंटित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब चार गुना ज्यादा है। केंद्र की सब्सिडी बढ़ने से राज्य के लाखों ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के काम में तेजी आएगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुशंसा पर राजस्थान के लिए यह राशि मंजूर की है। जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश में लगभग 9.97 लाख घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2024 तक शेष 80 लाख घरों में नल से पेयजल सप्लाई करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अब तक 54 पानी टैस्ट लैब भी खोली जा चुकी है।

ग्रामीण आवास योजना रहेगी जारी

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत वर्ष 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है। इसमें से नवम्बर 2021 तक 1.65 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य बेघर लोगों को आवास प्रदान करना है।

इस योजना के तहत मार्च 2021 तक 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें से केंद्र ने 1.44 लाख करोड़ रुपए तथा शेष राशि राज्य सरकारों ने खर्च की है। केबिनेट ने इस योजना के लिए 2.17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है।

प्रदेश के चार जिलों में आधे से ज्यादा गरीब

नीति आयोग की ओर से पहली बार गरीबी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक राज्यों में जहां बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबी है, वहीं राजस्थान में भी गरीबी के आंकड़े चौंकाने वाले साबित हुए हैं। यहां कुल आबादी के मुकाबले 29.46 फीसदी प्रदेशवासियों को गरीबी में गुजर बसर करना पड़ रहा है।

जारी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो गरीबी में राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। यहां शहरी क्षेत्र में 11.52 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 35.22 फीसदी आबादी गरीब हैं। प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले तो ऐसे है जहां आधी से भी ज्यादा आबादी गरीबी में अपना जीवनयापन कर रही है। प्रदेश में आज भी 42 फीसदी लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं और 35 फीसदी आबादी के पास अपना घर तक नहीं है।

जैविक खेती शुरू की अपनाए नवाचार

प्रदेश में 'कट्स' द्वारा संचालित प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के अन्तर्गत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों से प्रेरित होकर किसान जैविक खेती के माध्यम से कई नवाचार अपना रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं भीलवाड़ा जिला के फूलियाकला गांव के सुरेंद्र नागर व उनकी पत्नी विमला देवी, जिन्होंने पपीता की स्वदेशी किस्म 'पूसा नन्हा' की पौध तैयार की और खेत में 300 पौधे लगाकर भरपूर फसल ले रहे हैं। पपीतों की भीलवाड़ा, अजमेर आदि कई जिलों में अच्छी मांग है।

वह अपने खेत पर खुद गाय के गोबर, गो-मूत्र और केंचुओं से जैविक खाद बनाते हैं और उससे पैदावार बढ़ाने में लगे हैं। फसल को रोगों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों की बजाय वह गो-मूत्र आदि से खुद 'जीवामृत' कीटनाशक दवा भी तैयार करते हैं। जैविक खेती से उन्होंने जौ, गेहूं, मेथी, दालों आदि की पैदावार भी बढ़ाई है।

चिरंजीवी बीमा योजना से जुड़ेंगे परिवार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ रुपए के प्रावधान की मंजूरी दी है। अभियान का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज का लाभ देना है, ताकि उन्हें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके।

सरकार की ओर से चलाए जाने वाले इस अभियान में आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायतकर्मी फील्डस्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। वह अपने क्षेत्र में सर्वे कर यदि रजिस्ट्रेशन से वंचित पांच परिवारों को योजना से जोड़ेंगे तो उन्हें 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सुधर रही है खेतों की मिट्टी की सेहत

भारत सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। योजना के तहत किसानों की हर जोत के जीपीएस आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन कार्डों में भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों एवं विकारों को ध्यान में रख कर फसल के अनुसार किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उर्वरक की सलाह दी जा रही है। अब तक देश के 22 करोड़ 56 लाख किसानों को कार्ड वितरित कर दिए गए हैं।

योजना के तहत देश में 429 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 102 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 8452 सूक्ष्म मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मृदा परीक्षण का काम कर रही है। मृदाकार्ड बांटने के बाद के सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि उर्वरक की खपत 8 से10 फीसदी कम हुई है और फसलों की उपज में 5 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

महिलाओं व बच्चों को मुफ्त औषधि

निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए महिलाओं और बच्चों को एक जनवरी से निःशुल्क औषधियां मिलेंगी। स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को एनिमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से मुक्त करने के लिए अभियान चलाकर औषधियों का वितरण किया जाएगा।

यह जानकारी आयुर्वेद मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने देते हुए कहा कि प्रदेश के 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुष चिकित्सालयों को शीघ्र क्रियाशील करने और 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर